कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में माहशीर प्रजाति के विकास की संभावना को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल में माहशीर हैचरी की स्थापना के लिए अगस्त, 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मंत्रायल की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 की अपनी वार्षिक योजना में माहशीर के संबंध में एक योजना शामिल की थी। राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल में एक जगह का चयन भी कर लिया था तथा हैचरी निर्माण के लिए 16.48 लाख रुपए जारी किए थे। इसके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए माहशीर मात्स्यिकी विकास को योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

Access of Farmers to internet

4017. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Director General of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) had recently announced in Hyderabad that farmers would have access to Internet;

(b) whether the ICAR has conducted any survey to identify those farmers who have access and knowledge of computers and Internet;

(c) if so, what is the estimated number of farmers who would be surfing their computers for information on agriculture developments;

(d) whether ICAR would formulate more such schemes in future; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir. ICAR proposes connectivity of KVKs under the ninth plan as well as under NATP through which networking would be accomplished for information dissemination to the farmers to be trained in these KVKs.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e) ICAR has formulated schemes to provide computer and Networking equipment for Internet access under NATP to 40 Agricultural Technology Information Centres (ATIC) and 53 Zonal Research Stations (ZRS) which are also performing functions of KVKs, in phased manners. Twenty four KVKs, are located in 24 ATMA districts located in six states namely Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab and Orissa. Electronic connectivity to research and extension centres is envisaged under NATP at an estimated outlay of Rs. 90.0 crores, as well as, under the 9th plan for which detailed proposals are being worked out.

Integrated Pest Management in Andhra Pradesh

4018. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ICAR has concluded that Integrarted Pest Management (IPM) in Andhra Pradesh was not upto the mark;

(b) if so, what was the means used by ICAR to assess and arrive at this conclusion about IPM;

(c) whether ICAR has proposed any changes in the present system; and

(d) the details of ICAR's plan for improving Integrated Pest Management in the state?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) ICAR had constituted a high level committee to investigate the causes of crop failures, particularly cotton in Andhra Pradesh. The Committee after visiting the affected areas and interacting with farmers and developmental officers had in its report observed that the farmers do not seem to be aware of any IPM methods and their knowledge is limited in most cases to use of pesticides only.

(c) Yes, Sir.

(d) The ICAR committee in its report has suggested both short and long time IPM measures for management of pests of cotton. These include, setting up of a state level committee for regular pest monitoring, timely availability of quality inputs such as bioagents and biopesticides, stringent quality control for chemicals, training programmes and provision

of adequate manpower by the state and the need for public awareness campaigns through mass media and farmers' meetings. These have been communicated to all the concerned Central and State agencies.

गुजरात में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना

4019. **श्री चीमनभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कच्छ, राजकोट बनासकांठा जैसे जिलों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) क्या कच्छ जिले में उक्त परियोजना के अंतर्गत वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वांछित लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): कच्छ जिले में 14378 हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र के उपचार करने के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में, आठवीं योजना के दौरान बताई गई उपलब्धि 10980 हैक्टेयर रही जो 76 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ): वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई कमी के कारण हैं :—

(i) आठवीं योजना के दौरान शुरू की गई वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना पूर्व में क्रियान्वित किए जा रहे पनधारा कार्यक्रम का पुनर्गठित रूप था, इसमें फील्ड कार्यकर्त्ताओं और पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग को वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के कार्यान्वयन के शुरूआती चरण में परियोजना की अवधारणा, दृष्टिकोण, नीतियों और कार्यक्रम संबंधी विभिन्न उपायों की ओर अभिमुख किए जाने और प्रशिक्षित किए जाने में कुछ समय लगा, और

(ii) एनडब्ल्यूडीपीआरए के तहत आने वाले वास्तविक क्षेत्र के कवरेज में कृषि योग्य और गैर-कृषियोग्य भूमि का उपचार शामिल है।

पंचायतों/सरकारों के स्वामित्वाधीन गैर-कृषियोग्य भूमि के उपचार में संबंधित एजेंसियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में कुछ प्रक्रियात्मक देरी हुई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उपरोक्त बाधाओं को दूर किया जा रहा है।

ड्रिप सिंचाई के लिए गुजरात को धनराशि का आबंटन

4020. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात में कच्छ और बनासकांठा जिलों के लिए ड्रिप सिंचाई योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आबंटन में वृद्धि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धनराशि के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी गई है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने कच्छ और बनासकांठा में वर्तमान सूखे की स्थिति के संदर्भ में सरकार को सूचित किया है; और

(च) राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत सरकार निधियों का आबंटन राज्य सरकारों को करती है जो इसे देश के विभिन्न जिलों को आबंटित करती हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को आबंटित निधियों और तदनन्तर राज्य सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा जिलों को आबंटित निधियों के विस्तृत ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात सरकार ने 26.07 लाख रूपये के मूल आवंटन की तुलना में 315.00 लाख रूपये के आवंटन का अनुरोध किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।